

भारत की महानता में भूगोल के महत्व का एक अध्ययन

Dr. Chandra Prakash Verma

Asst. Professor. Geography

Department of Geography

H.S.B.Govt. P.G. College

Someshwar (Almora) Uttarakhand

सारांश, भारत में राजनेता, राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में वर्णित करने में गर्व महसूस करते हैं, और कई सामाजिक वैज्ञानिक देश के विशाल आकार और क्षेत्रीय मतभेदों और असमानताओं के कारण स्वाभाविक रूप से इस दृष्टिकोण को मानते हैं। इस प्रकार, भूगोल और भूगोलवेत्ताओं के पास तर्कसंगत विवरण देने और देश के संसाधनों, परिवर्तन की गतिशीलता और विकास प्रक्रियाओं के पैटर्न को समझाने की व्याख्या करने में एक बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य से भूगोल को हर जगह अंतिम प्राथमिकता मिलती है जब किसी विश्वविद्यालय में संकाय स्थापित होते हैं। इस प्रकार इस देश में इसकी शुरुआत बहुत देर से हुई है, और निश्चित रूप से यह तब भी सच है जब हम यूनाइटेड किंगडम और महाद्वीप और यू.एस.ए. में भूगोल के इतिहास को देखते हैं। भूगोलवेत्ताओं को विश्वविद्यालय में भूगोल का एक विभाग व्यवस्थित करने के लिए रणनीतिक लॉबी का संघर्ष करना और विकसित करना पड़ता है। यह अब और भी वास्तविकता है जब नीति निर्माताओं और अधिकारियों ने ज्ञान के विषयों को उपयोगिता और अनुपयोगी विषयों के रूप में वर्गीकृत करने पर एक अवैज्ञानिक और भयावह दृष्टिकोण विकसित किया है, और वे भूगोल को अनुपयोगी विषयों में से एक के रूप में नामित करने में जल्दबाजी करते हैं।

मुख्य शब्द, भूगोलवेत्ताओं, विश्वविद्यालय, अभिभावकों, छात्र, प्रतियोगी परीक्षा आदि।

प्रस्तावना, भूगोल का आगमन भूगोल को 1920 में पंजाब विश्वविद्यालय में, 1927 में पटना विश्वविद्यालय में और 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कॉलेजों में अध्ययन के विषय के रूप में खोला गया था। इसके बाद 1950 के दशक तक भूगोल का बहुत धीमी गति से प्रसार हुआ। भूगोल विभाग 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, 1947 में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में, 1948 में मद्रास विश्वविद्यालय में और 1957 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में खोला गया। भूगोल को उत्तर से दक्षिण तक फैलने में एक चौथाई सदी से अधिक समय लगा। भूगोल में पहला स्नातकोत्तर विभाग 1931 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खोला गया था। भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के खुलने की तिथियों का एक त्वरित सर्वेक्षण बताता है कि एक स्नातक विभाग

को स्नातकोत्तर विभाग बनने में औसतन लगभग 20 वर्ष लगते थे। उदाहरण के लिए, मद्रास विश्वविद्यालय में भूगोल में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम 17 वर्षों तक चला। स्नातकोत्तर विभाग स्थापित होने से पहले। 1930 और 1950 के बीच, केवल आठ विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग थे। 1952 के बाद से, अधिक से अधिक विभाग, विशेष रूप से हिंदी पट्टी और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, भूगोल के लिए खोले गए। 1980 के दशक तक, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने भूगोल विभाग स्थापित कर लिए थे। गंगा के क्षेत्र में भूगोल विभाग खोलने के प्रति प्रतिक्रिया अधिक उत्साहजनक प्रतीत होती है, और यहाँ भूगोल को छात्रों और अभिभावकों द्वारा सामान्य ज्ञान के एक विषय के रूप में बहुत महत्व दिया गया है जो छात्रों को सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में मदद करता है। दक्षिण भारत में, जहाँ विज्ञान विषयों को छात्रों और अभिभावकों द्वारा अधिक महत्व दिया जाता है, भूगोल का प्रसार कम है। केरल राज्य, एक दक्षिणी पर्वतीय राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, साक्षरता स्तर देश में सबसे अधिक है, पलायन काफी अधिक होता है, और संसाधनों का प्रबंधन खराब है, वहाँ अभी भी भूगोल के लिए कोई विश्वविद्यालय विभाग नहीं है। भारतीय भूगोल के इतिहास में, क्रांतियों के उदाहरण नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के बिंदु रहे हैं।

भारतीय भूगोल के इतिहास में पहला मील का पत्थर, जैसा कि कहा गया है, 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना थी। 1956 में, इस देश में विषयगत मानचित्रण प्रकाशित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय एटलस संगठन (एनएओ), कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रो.एस.पी. चटर्जी के प्रयासों से स्थापित किया गया था। एनएओ का नाम बदलकर बाद में राष्ट्रीय एटलस और विषयगत संगठन (अब एनएटीएमओ के रूप में लोकप्रिय) रखा गया। 1960 के दशक में पांडिचेरी के फ्रेंच इंस्टीट्यूट में कार्टोग्राफिक यूनिट के संगठन ने भारत में भूगोल के विकास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और 1:100000 के पैमाने पर वनस्पति और मृदा मानचित्रों के इसके प्रकाशन को इसके कार्टोग्राफिक मूल्यांकन और संसाधन मानचित्रण के लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस यूनिट को 1995 में कंप्यूटर कार्टोग्राफी और जीआईएस पर जोर देते हुए जियोमैटिक्स प्रयोगशाला के रूप में उन्नत किया गया।

1968 में नई दिल्ली में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ सम्मेलन ने भारतीय भूगोलवेत्ताओं के एक बड़े वर्ग को दुनिया के विभिन्न हिस्सों के भूगोलवेत्ताओं के साथ बातचीत करने और इस प्रकार भारत के तटों से परे अपने भौगोलिक दृष्टिकोण और समझ के क्षितिज का विस्तार करने का अवसर दिया। 1970 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र की स्थापना ने भारत में भौगोलिक अनुसंधान में एक अंतःविषय दृष्टिकोण शुरू करने और भूगोल के अस्तित्व के लिए भौगोलिक अनुसंधान की सामाजिक प्रासंगिकता पर जोर देने और भारतीय भौगोलिक अध्ययनों का भारतीयकरण करने में मदद की। वर्ष 1980 भारतीय भूगोल के लिए एक और महान क्षण था और उस वर्ष, राष्ट्रीय भूगोल संघ, भारत (जिसे एनएजीआई के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई। की स्थापना

भारतीय भूगोलवेत्ताओं को भारतीय भूगोल और भूगोलवेत्ताओं के एक ही झंडे तले एकजुट करने के लिए की गई थी, जिसका श्रेय समकालीन भूगोल की तीन महान हस्तियों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. मूनिस रजा (दुर्भाग्य से जिनका कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया), बॉम्बे विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ राजनेता और भूगोलवेत्ता प्रो. सी.डी. देशपांडे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली के प्रो. एल.एस.भट की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों को जाता है। भौगोलिक सोसायटी और जर्नल हमेशा से शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भौगोलिक अध्ययन को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। भारत में भौगोलिक सोसायटी का इतिहास लगभग 150 वर्षों का है। विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना से भी पहले, 1832 में बॉम्बे (अब मुंबई) में ब्रिटिश पहल के साथ एक भूगोल सोसायटी, बॉम्बे ज्योग्राफिकल एसोसिएशन को बढ़ावा दिया गया था 1925 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पहली बार भूगोल के प्रचार-प्रसार के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय में एक सोसायटी को संगठित करने का रास्ता दिखाया।

भारत में भूगोल के प्रचार-प्रसार की दिशा में सोसायटी की गतिविधियों की वास्तविक शुरुआत 1926 में चेन्नई (तब मद्रास) में मद्रास प्रांत के टीचर्स कॉलेज के प्रो. एन. सुब्रमण्यन के कुशल नेतृत्व में भारतीय भौगोलिक सोसायटी की स्थापना के साथ देखी गई थी। अपनी त्रैमासिक पत्रिका, द मद्रास ज्योग्राफिकल जर्नल (उसी वर्ष 1926 में शुरू हुई अब भारतीय भौगोलिक जर्नल) के साथ, भारतीय भौगोलिक सोसायटी ने भारत में भूगोल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला स्तर की संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित करके और तत्कालीन मद्रास प्रांत के विभिन्न जिलों के क्षेत्रीय भूगोल पर लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करके क्षेत्रीय भूगोल की विषयवस्तु को विकसित करने में सोसायटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1933 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कलकत्ता ज्योग्राफिकल सोसायटी को बढ़ावा दिया और 1936 में अपनी पत्रिका, जियोग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया शुरू की।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1946 में नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू किया और यह ज्योग्राफिकल सोसायटी प्रोफेसर आर.एल. सिंह के सक्रिय नेतृत्व में देश की एक संसाधन संपन्न सोसायटी के रूप में विकसित हुई। 1948 में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ समन्वय करने के लिए, एक संगठन, काउंसिल ऑफ ज्योग्राफर्स, इंडिया को उन भूगोलवेत्ताओं द्वारा बढ़ावा दिया गया, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस वैज्ञानिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और राष्ट्रीय सरकार के अच्छे समर्थन के साथ, देश में विज्ञान में अनुसंधान की प्रगति को प्रदर्शित करने और चर्चा करने के लिए साल में एक बार मिलता है। 1953 में, बॉम्बे ज्योग्राफिकल जर्नल की स्थापना की गई और कुछ वर्षों की सेवा के बाद, इसे दुर्भाग्य से बंद कर दिया गया। भारत में कई अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थान भी भूगोल के प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन, भारत की जनगणना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय योजना आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भूमि उपयोग प्रभाग और राष्ट्रीय

सुदूर संवेदन एजेंसी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो भूगोल से बहुत प्रासंगिक हैं, और वे इस देश में भूगोल के विकास में मदद कर रहे हैं। राज्य स्तर पर, राज्य के योजना आयोग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और महानगर विकास प्राधिकरण कुछ ऐसे विभाग हैं जो भूगोल के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। भारतीय भूगोल के विकास के चरण 1920 के दशक में पंजाब में इसकी शुरुआत के बाद से भारत में भूगोल का इतिहास केवल सात दशकों का है। भारतीय भौगोलिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपत्रों के सर्वेक्षण से इस देश में भूगोल विषय के विकास के चार निश्चित चरण ज्ञात होते हैं, 1950 से पहले, 1950–1970, 1971–1990 और 1990 के बाद। 1950 से पहले की अवधि, पहला चरण, वर्णनात्मक अध्ययनों द्वारा चिह्नित था जिसमें भौतिक परिदृश्य पर अधिक जोर दिया गया था गजेटियर प्रकार का वर्णनात्मक लेखन आम था अनुसंधान को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था और स्कूल स्तर और स्नातक स्तर पर भूगोल के शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया था।

दूसरे चरण, 1950–1970 के दौरान, विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक भूगोल विभाग स्थापित हुए और इस तरह भूगोल में स्नातकोत्तर अध्ययन व्यापक हो गए परिणामस्वरूप भौगोलिक अध्ययन में अनुसंधान को भी प्राथमिकता मिली और ये अध्ययन प्रकृति में अधिक विश्लेषणात्मक और दृष्टिकोण में व्याख्यात्मक थे। इस अवधि में, भौगोलिक संघों और पत्रिकाओं का प्रसार हुआ था, विशेष रूप से गंगा क्षेत्र में, और भौगोलिक पत्रिकाएँ हिंदी भाषा में भी आने लगी थीं, जो उत्तर भारत की प्रमुख भाषा थी।

तीसरे चरण (1971–1990) में, मौजूदा भूगोल विभागों का संकाय और छात्रों के संदर्भ में विस्तार हुआ निगमनात्मक दृष्टिकोण अधिक लोकप्रिय हो गए और इसलिए मात्रात्मक तरीकों को अक्सर अपनाया गया। उत्तर भारत में, कई विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भूगोल के शिक्षण का माध्यम हिंदी में बदल दिया गया, और शोधकर्ताओं ने हिंदी में पीएचडी शोध प्रबंध लिखना शुरू कर दिया।

वर्तमान चरण (1990 के बाद) को कंप्यूटर और कंप्यूटर-सहायता प्राप्त मानचित्रण, अंतःविषय दृष्टिकोणों और सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान पर जोर के व्यापक उपयोग की विशेषता थी। भौगोलिक शोध अध्ययन भारतीयकृत हो गए। उत्तर में भूगोल का हिंदी-भारतीयकरण जारी है, और दक्षिण और पूर्व में, भूगोल अभी भी स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, और एम.फिल और पीएचडी शोध प्रबंध अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। भूगोलवेत्ता हमेशा किसी भी नए उपकरण या तकनीक को अपनाने में तत्पर रहते हैं, और भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने वैश्विक राजमार्ग, इंटरनेट के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान भारत में भूगोल के विकास में, यूरोपीय और अमेरिकी दृष्टिकोणों की छाप देखी जा सकती है। प्रथम चरण के कई भूगोलवेत्ताओं, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो.एस.पी.चटर्जी और मद्रास विश्वविद्यालय के प्रो.जॉर्ज कुरियन ने अपनी शिक्षा ग्रेट ब्रिटेन में प्राप्त की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो.शफी ने ग्रेट ब्रिटेन में डुडले स्टैम्प के भूमि उपयोग अध्ययनों का अनुसरण किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो.आर.एल.सिंह, जो अपने बस्ती अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, रांची विश्वविद्यालय के प्रो.ई.अहमद,

जो अपने भू-आकृतिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के प्रो.एम.पी.टाकोरे और उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रो. आलम, जो अपने शहरी अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपनी शिक्षा यूनाइटेड किंगडम में प्राप्त की थी। द्वितीय चरण के कई भूगोलवेत्ताओं ने अपनी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की थी।

पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो.गोसल और प्रो.ए.बी.मुखर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो.रामचंद्रन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो.सी.आर.पाठक हाल के दिनों में भारतीय भूगोल का विकास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से काफी प्रभावित था और यह भारतीय भूगोल का तीसरा चरण हो सकता है। गंगा बेल्ट और मध्य भारत के विश्वविद्यालयों में भूगोल की कुर्सियों पर बैठे कई भूगोलवेत्ताओं ने या तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. ए. अहमद, जो भूगोल में सामाजिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रो. रमेश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी।

भारतीय भौगोलिक अध्ययन के रुझान भौतिक भूगोल भू-आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान को सभी विश्वविद्यालयों में भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य पेपर के रूप में माना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मृदा और हिमनद अध्ययन पर पर्याप्त शोध किया है। रांची विश्वविद्यालय के प्रो. ई. अहमद द्वारा तटीय भू-आकृतियों पर अध्ययन, प्रो. के.आर. दीक्षित द्वारा भू-आकृतियों के विकास पर अध्ययन ना विश्वविद्यालय के प्रो. सविंद्र सिंह द्वारा नदीय भूआकृति विज्ञान पर किए गए अध्ययन, और प्रो. पद्मजा द्वारा उष्णकटिबंधीय भूरूपों पर किए गए अध्ययन सुप्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश का वाल्टेयर विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान और भूआकृति विज्ञान में अपने अध्ययनों के लिए जाना जाता है, और प्रो. वी.पी. सुब्रमण्यम द्वारा जल संतुलन संबंधी अध्ययन और प्रो. वैद्यनाथन द्वारा सुदूर संवेदन उत्पादों की दृश्य व्याख्या की सहायता से भूरूपों की पहचान के अध्ययन उद्धृत करने योग्य हैं। केरल के पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, राजस्थान के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और असम विश्वविद्यालय में भूआकृति संबंधी अनुसंधान सक्रिय रूप से चल रहा है।

वर्तमान में भूआकृति संबंधी अनुसंधान के लिए सुदूर संवेदन उत्पादों का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है और अधिकतर दृश्य व्याख्या की जाती है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी बिम्बों और हवाई तस्वीरों के साथ भूआकृति विज्ञान के मॉडल अध्ययन विकसित करने में सक्रिय है पर्यावरण एवं संसाधन अध्ययन: योजना आयोगों की रुचि और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी और सुदूर संवेदन संस्थान की पहलों के कारण भूगोलवेत्ताओं के बीच पर्यावरण और संसाधन अध्ययन के प्रति व्यापक रुचि रही है। भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण और भूगोल पर्यावरण और सतत विकास के प्रति वर्तमान चिंता के कारण ईआईए अध्ययन अक्सर किए जाते हैं। संसाधन सूची, दोहन और संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव पर अध्ययन होते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग ईआईए के अध्ययन और भूमि उपयोग अध्ययन के लिए सुदूर संवेदन उत्पादों के उपयोग के शुरुआती विभागों में से एक है। मानव/आर्थिक भूगोल: एक कृषि

प्रधान देश होने के नाते, भारत में कई विश्वविद्यालयों में भूगोलवेत्ताओं के लिए कृषि भूगोल अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कृषि भूगोल के अध्ययन में अग्रणी है। भूमि उपयोग, फसल-संयोजन, फसल और कृषि क्षेत्र, फसल उत्पादकता, कृषि दक्षता और पोषण पर अध्ययन बहुत आम हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र कृषि विकास में क्षेत्रीय अंतरों के अध्ययन में अधिक रुचि लेता है और कृषि उत्पादकता एवं विकास में क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या करने के लिए सामाजिक एवं संस्थागत कारकों पर जोर देते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। कृषि क्षेत्रीयकरण की मात्रात्मक पद्धति और वॉन थुनेन के फसल स्थान और कृषि उत्पादन के सिद्धांत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ताओं का ध्यान भी आकर्षित किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शहरी और ग्रामीण अध्ययनों सहित बस्ती भूगोल पर अपने योगदान के लिए जाना जाता है। देश के अधिकांश शहरी भूगोलवेत्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शहरी अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति पर अमेरिकी प्रभाव काफी हद तक देखा जा सकता है। मद्रास विश्वविद्यालय ने स्थान विश्लेषण और शहरी पारिस्थितिकी पर, और हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय ने महानगरीय अर्थव्यवस्था, औद्योगीकरण और शहरीकरण पर अध्ययन किए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र ने भारत में वस्तु प्रवाह के विश्लेषण पर बी.जे.एल.बेरी के अध्ययन के बाद, द्वितीयक आँकड़ों के साथ भारत में व्यापार और परिवहन पर एक मात्रात्मक अध्ययन किया है।

भारत की जनगणना से प्राप्त एक उचित डेटाबेस की उपलब्धता के कारण, जनसांख्यिकी अध्ययनों ने भी देश भर के कई भूगोलवेत्ताओं को आकर्षित किया है। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. गोपाल किशन जनसंख्या भूगोल पर अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र के जनसंख्या प्रकोष्ठ ने सांख्यिकी के विद्वानों के साथ-साथ कई भूगोलवेत्ताओं को जनसंख्या अध्ययन पर कार्य करने के लिए आकर्षित किया है। जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, अनुसूचित जाति और जनजाति के वंचित समुदाय और जनसांख्यिकीय चरों में क्षेत्रीय विविधताएँ भूगोलवेत्ताओं के लिए चिंता के कुछ विषय हैं। ऐतिहासिक भूगोल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन में निरंतर रुचि दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. मूनिस रजा, प्रो. ए. अहमद और प्रो. एम.एच. कुरैशी ने भूगोल के विद्वानों को ऐतिहासिक भूगोल पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने में गहरी रुचि दिखाई। आमतौर पर महाकाव्य, यात्रा दस्तावेज और मुगल लेखन इन अध्ययनों के लिए सामग्री के स्रोत होते हैं।

बॉम्बे विश्वविद्यालय के प्रो. बी. अरुणाचलम तमिलनाडु के चोल राजाओं के इतिहास, उनकी प्रशासनिक संरचना और नौसैनिक गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत का एटलस, जो पाषाण युग से लेकर 1977 तक के इतिहास का पता लगाता है, भारत और दक्षिण एशिया में रुचि रखने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में से एक, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रो. शार्ल्सबर्ग द्वारा किया गया एक स्मारकीय कार्य है। क्षेत्रीय नियोजनरू पंचवर्षीय योजनाओं

के दौरान आर्थिक नियोजन ने संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय नियोजन और खंड विकास दृष्टिकोण को मान्यता दी। क्षेत्रीय नियोजन और क्षेत्रीयकरण की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र क्षेत्रीयकरण, क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय नियोजन के अध्ययनों में निरंतर रुचि ले रहा है।

भारतीय भूगोल की वर्तमान स्थिति दुनिया के अन्य स्थानों की तरह, भूगोल विभागों में भौतिक भूगोल का शिक्षण जारी है, हालाँकि भौतिक भूगोल में कोई गंभीर शोध कार्य अब कम ही होता जा रहा है। कई भूगोल विभागों ने स्नातकोत्तर भूगोल के शिक्षण से सर्वेक्षण की विषयवस्तु और डम्पी लेवल और थियोडोलाइट सहित सर्वेक्षण उपकरणों के उपयोग को हटा दिया है। कुछ संगोष्ठियों और सम्मेलनों में कुछ गंभीर प्रतिभागियों को यह टिप्पणी करते हुए सुनना असामान्य नहीं है कि भूगोल शिक्षण नीरस और नीरस हो गया है, और शिक्षण की गुणवत्ता खराब हो गई है। बेशक, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में यह व्यापक धारणा और चिंता है कि शिक्षा का सामान्य स्तर अब बहुत खराब हो गया है। भूगोल एक क्षेत्र विज्ञान है, लेकिन भूगोलवेत्ता अब आरामकुर्सी भूगोलवेत्ता बन गए हैं। अब क्षेत्र कार्य पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है या क्षेत्र कार्य अक्सर भ्रमण बन जाते हैं, हालाँकि इसे अक्सर भूगोल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं के मानचित्रण कौशल में चिंताजनक रूप से गिरावट देखी जा रही है और कई बार भूगोलवेत्ता अपने मानचित्रण कार्यों के लिए ड्राफ्ट्समैन पर निर्भर रहते हैं। पिछले कई वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय मानचित्रण संघ के सेमिनारों में भूगोलवेत्ताओं की भागीदारी बहुत कम रही है। क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन में रुचि घट रही है।

निष्कर्ष, भूगोलवेत्ताओं ने सहज ही स्वीकार कर लिया है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है और इसीलिए भौगोलिक अन्वेषणों में मात्रात्मक विधियों और बहुभिन्नरूपी सांख्यिकी का व्यापक और लगातार उपयोग किया जा रहा है। भौगोलिक अनुसंधान के लिए बहु- और अंतःविषयक दृष्टिकोण स्वीकार किए जाते हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों के भौगोलिक पाठ्यक्रम में सुदूर संवेदन को शामिल कर लिया गया है। पिछले लगभग पाँच वर्षों में, भारतीय भूगोलवेत्ताओं में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में व्यापक जागरूकता फैली है। मद्रास विश्वविद्यालय भूगोल में अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर जीआईएस को शामिल करने वाले अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। निस्संदेह, सुदूर संवेदन और जीआईएस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग संस्थान आगे बढ़ रहे हैं, हालाँकि केवल भूगोलवेत्ता ही इन उपकरणों को अधिक सार्थक बना सकते हैं। सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन सामान्यीकरण का प्रयास कम ही किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक अन्वेषण करना भारतीय भूगोलवेत्ताओं के लिए हमेशा से एक दुःस्वप्न रहा है, और दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति जारी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 डाहलमैन, कार्लय रेनविक, विलियम (2024) भूगोल का परिचय लोग, स्थान और पर्यावरण (छठा संस्करण)

- 2 बर्ट, टिम (2023) भूगोल में प्रमुख अवधारणाएँ भौतिक भूगोल में पैमाना, विभेदन, विश्लेषण और संश्लेषण (दूसरा संस्करण) जॉन विले एंड संस पृष्ठ 85–96
- 3 साला, मारिया (2024) भूगोल खंड IA ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम EOLSS यूनेस्को रोलर,
- 4 डुआने डब्ल्यू. (2020). एराटोस्थनीज का भूगोल. न्यू जर्सी रू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
- 5 ब्रेटजेस, सोनजा (2021). इस्लामिक समाजों में मानचित्रकला. मानव भूगोल का अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश. एल्सेवियर. पृ. 414–427.
- 6 कर्ट ए. राफलौब और रिचर्ड जे. ए. टैलबर्ट (2022). भूगोल और वंशविज्ञान पूर्व–आधुनिक समाजों में विश्व की धारणाएँ. जॉन विले एंड संस. पृ. 147.
- 7 थ्रिपट, निगेल (2019) भूगोल में प्रमुख अवधारणाएँ अंतरिक्ष, भूगोल का मूलभूत तत्व (द्वितीय संस्करण) जॉन विले एंड संस पृष्ठ 85–96